

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1769
उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी

1769. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की संख्या का जिला-वार/तहसील-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस सेवा से अभी भी वंचित पंचायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए सरकार द्वारा आज तक आवंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने शेष ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रावधान किया है; और
- (च) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) भारतनेट चरण-1 एवं II के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के दौरान 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में सरकार ने 1.88 लाख करोड़ रूपए के परिव्यय से सभी बसे हुए गांवों को शामिल करने के लिए भारतनेट कार्यक्रम में संशोधन किया है जो निम्नानुसार है:

- i) मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन

- ii) भारतनेट उद्यमियों अर्थात् ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से नेटवर्क का उपयोग करने पर फोकस।
- iii) 10 वर्षों के लिए व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से सम्पूर्ण नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव।
- iv) समर्पित नेटवर्क प्रचालन केंद्र।
- v) सभी बसे हुए गांवों के जोड़ने के लिए कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।
- vi) 1.5 करोड़ होम फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराना।

(घ) से (च) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत निधि का संवितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार किया जाता है। महाराष्ट्र में दिनांक 31.10.2023 तक ठाणे जिले सहित भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के अंतर्गत 4605.46 करोड़ रु. और प्रचालनात्मक व्यय (ओपेक्स) अंतर्गत 355.52 करोड़ रु. संवितरित किए जा चुके हैं। संबंधित ब्यौरा दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
